Uttarakhand Civil Judge (Mains) 2016

भाषा (Language) · compulsory paper

Time allowed: Three Hours · Maximum Marks: 100
निर्धारित समय : तीन घण्टे · पूर्णांक : 100

Part - I

1. Translate the following English passage into the ordinary language spoken in courts, using Devnagri Script : Marks not printed

Legal profession is a significant aspect of the administration of justice. Without a well organized profession of law, the courts would not be in a position to administer justice effectively. The facts of the case can not be put forth before the courts of law, evidence in favour or against the parties to a suit can not be properly adduced and legal arguments in support or against the parties can not come up properly before a court of law without the assistance of a lawyer.

In our country, in the pre-independence era and in the more than six decades following independence, the Bar participated actively in the activities of the nations mainstream. There were lawyers of outstanding ability, leadership and social commitment. They contributed a lot by making memorable sacrifices in the national freedom movement. But in the present state of affairs, the legal profession has been rapid decline in the quality of Bar with gradual exit of the old legal luminaries. What is the state of the Bar today? The atmosphere is full of frustration, suspicion, disorganization, dissatisfaction, cut-throat competition, etc. Thus, the legal profession is passing through a painful phase.

India is in process of planned development through Five Year Plans. We are passing from medieval to the modern industrial society. We have adopted the socialist pattern of society. Our government aims at a welfare state. Our problems are acute and more complicated as compared to the past. Therefore, the role and responsibilities of the lawyers have also taken a changed shape.

Lawyers should behave themselves in a manner befitting their status as an officer of the court. An advocate shall fearlessly uphold the interests of the client both in letter and in spirit.

There are three characteristics of the legal profession : group organization, learning and a spirit of public service. For lawyers, the most important truth about the law is that it is a profession and not a business. Therefore, the legal profession must ignore commercial standards of success. The legal profession helps the court to administer justice in its manifold aspects. But as an organized profession, it must necessarily do much more. The legal profession in a democracy has to be a watchdog of freedom and the rights of the citizens. The profession must uphold the constitution and the liberties enshrined in it. It should promote and safeguard the dignity and independence of judiciary. At the same time, it should also operate as a check on the judiciary against any compromise which is not in consonance with the highest standards of judicial integrity and its independence.

The legal profession in our country should function as a watchdog against the assaults of the modern state whenever it seeks to curtail the basic human rights, which is a threat to freedom, democracy and the rule of law.

In the matter of providing free legal aid to the poor, the legal profession has a clear responsibility, a responsibility which unfortunately has not been discharged with even at the minimum expectation of the society. Although lawyers do individually provide legal advice and assistance in deserving cases,

there is an absence of countrywide organized efforts for free legal aid to the poor. The legal aid programme offers a historic and challenging social responsibility to the legal profession in India.

To conclude, we may say with firmness and certainty that there is a purposive social responsibility of the legal profession in a free and democratic society in which a lawyer has a function of public leadership. We must, however, understand that the legal profession can not function in vacuum or in isolation. Lawyers should come forward in the forefront of national life to establish rule of law without any discrimination whatsoever.

Part-II

2. निम्नलिखित हिन्दी गद्यांश का सामान्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। 30

Translate the following Hindi passage into ordinary English language :

न्यायिक सक्रियता का विभिन्न लोग विभिन्न अर्थ लगाते हैं। न्यायिक सक्रियता के बारे में विचार न केवल भिन्नता लिए हुए हैं अपितु लोगों के विचारों में व्यापक रूप से अन्तर्विरोध भी है। कुछ लोग इसे न्यायाधीशों की गतिशीलता, न्यायिक सृजनात्मकता का नाम देते हैं तो कुछ इसे न्यायपालिका द्वारा देश के कानूनों को लागू करने में दिखाई जाने वाली दृढ़ता के रूप में क्रान्ति का नाम देते हैं। कई अन्य लोग जो न्यायालयों द्वारा इस प्रकार शक्ति के प्रयोग को न्यायिक अतिवादिता के रूप में देखते हैं, तथा इसे न्यायालयों द्वारा न्यायिक शक्तियों का अवान्छित विस्तार मानते हैं, उनके द्वारा इसे न्यायपालिका द्वारा राज्य के अन्य अंगों की शक्तियों को हथियाना भी माना गया है।

न्यायालय जनहित के अनेक ऐसे मामलों में, जो कार्यपालिका एवं विधान-मण्डल के क्षेत्र में हैं, हस्तक्षेप कर रहा है और सरकार तथा प्राधिकारियों को संविधान एवं अन्य कानूनों के अन्तर्गत उनके कर्तव्यों के पालन करने के लिये विवश कर रहा है। उच्चतम न्यायालय की इसी कार्यवाही को "न्यायिक सक्रियता' कहा जाता है। यह इसलिए संभव हुआ है, क्योंकि लोकहित वाद के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध तथा कानून द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के पालन कराने के लिए न्यायालय में याचिकाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अब यह अनुभव किया है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य में उच्चतम न्यायालय इस नये अस्त्र का प्रयोग केवल निर्धन एवं असहाय नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए ही नहीं करेगा वरन् पूरे समाज को अपराधविहीन एवं व्यवस्थित समाज में परिवर्तित करने में करेगा। आज सामान्य नागरिक के लिये लोकहितवाद के माध्यम से न्यायिक सक्रियता वरदान साबित हुई है। इस बिन्दु पर मतभेद है कि न्यायिक सक्रियता का स्वागत किया जाय या इसको रोका जाय। लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग यह सोचता है कि न्यायिक सक्रियता सही दिशा की ओर उठाया गया कदम है, जो कि राज्य की अन्य संस्थाओं की निष्क्रियता या अधिकारिता युक्त कृत्यों द्वारा जनित विपदाओं का निराकरण करता है। वस्तुतः सक्रियता के दृष्टिकोण से न्यायपालिका आमूल-चूल सुधार करने वाली शक्ति बन गई है जबकि विधायिका और कार्यपालिका विद्यमान जड़ता युक्त स्थिति को बनाये रखने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं।

हमारे जैसी जनतान्त्रिक व्यवस्था में केन्द्र में संसद को तथा राज्यों में विधान-मण्डलों को जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिये, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो परिणामस्वरूप लोगों में जनतांत्रिक संस्थाओं के प्रति गहन असन्तोष उत्पन्न होगा और यही कारण है कि न्यायालय राज्य के अन्य अंगों को निद्रा से जगाने के लिए आगे आए हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि राजनैतिक दल मृत प्राय हैं या छिन्न-भिन्न हो रहे हैं, न्यायपालिका को बहुत सावधानीपूर्वक कार्य करना होगा। विधायिका और कार्यपालिका का कमजोर पड़ना न्यायपालिका को महत्वाकांक्षी कदम उठाने को प्रेरित करता है किन्तु यह उसे भली-भांति पता होना चाहिए कि वह राज्य के उन दो अंगों का स्थान नहीं ले सकती। आदर्श स्थिति वही होगी जब राज्य के कृत्यों का संचालन करने वाला प्रत्येक अंग संविधान के अधीन उन्हें सौंपे गये कृत्यों का ही निर्वहन करे।

हमारे संविधान में न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा उठाये गये उन कदमों को निष्क्रिय कर दे जिनके बारे में सावधानीपूर्वक जाँच करने एवं उनका निर्वचन करने के पश्चात् यह पाया जाय कि वे संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध हैं। वे नागरिक सुविधाएँ जिन्हें उपलब्ध कराने का दायित्व प्राधिकारी या संस्थाओं का है, यदि उपलब्ध नहीं की जाती हैं, तो उनकी प्राप्ति का मार्ग न्यायालयों ने सुलभ करा दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता से ही बिहार की जेलों में बंद कैदियों की स्थिति में सुधार आया, बम्बई की झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों की रक्षा की जा सकी, परीक्षणाधीन कैदियों को भी जेल में मूल अधिकार दिये गये, जिसके तहत उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता एवं शीघ्र परीक्षण प्राप्त करने का अधिकार मिला, नारी निकेतनों में महिलाओं के शोषण को रोका जा सका, बन्धुआ मजदूरों को मुक्ति दिलायी गई, 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया।

इन उपरोक्त निर्णयों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्देशों के माध्यम से न्यायिक सक्रियता को गतिशीलता प्रदान की है। यह न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के भाग-4 में वर्णित राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को अपने संवैधानिक विनिश्चयों द्वारा धीरे-धीरे मूल अधिकारों का दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया है तथा इसके माध्यम से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को संक्षण प्रदान किया है।

Part - III

3. निम्न गद्यांश का संक्षिप्तीकरण अंग्रेजी में कीजिए-

Write a precis in English of the following passage : Marks not printed

The Indian Independence Act, 1947 legally partitioned British India only. As far as the Indian States (including Jammu and Kashmir State) were concerned, accession was governed by the Cabinet Mission Plan of 1946. Under this plan, the Indian States were given the option of entering into federal relationship or political relationship with the successor governments. Accession could be completed on the execution of an Instrument of Accession. The right was conferred by the Government of India Act, 1935, which was the provisional Constitution of India at the time of independence. After partition, the then Jammu and Kashmir State chose not to enter either the dominion of India or of Pakistan, concluding instead, standstill agreements with both the countries. But Pakistan, in violation of this agreement, imposed an economic blockade on the State. Moreover, it launched an aggression in Poonch which became an all out invasion by October 22, 1947. Two days later, when telegrams to the Premiers of Pakistan and the United Kingdom proved futile and the Ruler of Kashmir appealed to India for help on October 24, 1947, he executed an Instrument of Accession in favour of India, which was accepted by the Government of India on October 27, 1947.

The Government of India was under no legal obligation to hold a plebiscite. Yet it was the Indian Government itself, which consistent with its policy of basing political arrangements on popular will, expressed a wish in a separate letter (it being not a part of the Instrument of Accession) by the Governor-General of India to the Ruler of Kashmir to refer the question of accession to the people of Kashmir. However, M.A. Jinnah rejected this offer and made a counter offer of joint administration of the State. In law, whenever a counter-offer is made, the earlier offer stands revoked, and as the CA counter-offer itself was not accepted, it too lapsed. All subsequent offers made by India also lapsed as their pre-conditions were never satisfied by Pakistan.

In any case, the Kashmir Ruler's decision to accede to India was unanimously backed by the biggest and most representative political party in Kashmir – The All Jammu and Kashmir National Conference which, in 1950, recommended for the convening of a Constituent Assembly for the state. The elections to the Constituent Assembly reaffirmed popular approval of the State's Accession, as did the adoption of the State's Constitution in November, 1956. This Constitution itself, stated that the State is and shall be an integral part of India.

Reference is sometimes made to Paragraph II of Jan. 5, 1949 UNCIP Resolution which referred to the holding of a plebiscite. However, this paragraph itself made the plebiscite conditional upon Paragraph

II of the August 13, 1949 Resolution and as Pakistan consistently committed breach of the same, India could not be compelled to hold a plebiscite under the 1949 Resolution.

Pakistan is guilty of aggression in Kashmir. This fact was exposed by the U.N. Commission itself as far back as 1948. What is required today is the negotiations with Pakistan not to determine the status of Kashmir but to free Indian territory from its forcible occupation.